कृषि–केंद्रित एनबीएफसी और फिन. टेक कृषि नवाचार के लिए ऋण आवश्यकता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं

श्री प्रभात चतुर्वेदी, सीईओ,
नेटाफिम एग्रीकल्चर फाइनेंसिंग एजेंसी प्रा. लिमिटेड (एनएएफए)

कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख क्षेत्र है, जिसकी लगभग 85 प्रतिशत कृषि जोत आकार में 2 हेक्टेयर से कम है, फिर भी हमारी 1.41 बिलियन की बड़ी आबादी के लिए पर्याप्त भोजन और फाइबर का उत्पादन करती है। इसके अलावा, यह कुछ शुद्ध निर्यात अधिशेष (अतिरिक्त) उत्पन्न करता है। यह किसानों को बड़े पैमाने पर ऋण प्रदान किए बिना संभव नहीं होता। विशेष रूप से छोटे और सीमांत किसानों के लिए, संस्थागत स्रोतों से पर्याप्त, समय पर, कम लागत वाले ऋण तक पहुंच आवश्यक है। नीति निर्माताओं ने ऋण के संस्थागत स्रोतों तक किसानों की पहुंच में सुधार के लिए कई उपाय शुरू किए हैं। इन नीतियों ने सभी किसानों को समय पर और पर्याप्त ऋण सहायता प्रदान करने के लिए प्रगतिशील संस्थानीकरण पर जोर दिया है। इस प्रकार, छोटे और सीमांत किसानों को कृषि पद्धतियों में सुधार करने में सक्षम बनाने पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है।

भले ही देश ने किसान समुदाय को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए कृषि–ऋण में सुधारों की शुरुआत में कुछ सक्रिय कदम उठाए हैं, फिर भी यह कुछ

पड़ोसी देशों की तुलना में पीछे है। जबकि दशकों में ऋण की मात्रा में सुधार हुआ है, इसकी गुणवत्ता और कृषि पर प्रभाव केवल कमजोर हुआ है। कृषि के लिए पर्याप्त पूंजी प्रतिबद्धता की आवश्यकता होती है, क्योंकि अधिकांश किसानों के लिए उपकरणों की खरीद एक महत्वपूर्ण व्यय है। फिर भी, किसानों को दिया जाने वाला अधिकांश कृषि ऋण कार्यशील पूंजी प्रकृति का है, इस प्रकार किसानों की 80 प्रतिशत से अधिक आय स्थिर है।

भारतीय ऋण मांग के विश्लेषण से पता चलता है कि भले ही बैंक और अन्य वित्तीय संस्थान आक्रामक रूप से प्राथमिकता क्षेत्र ऋण के तहत किसान समुदाय तक अपनी पहुंच बढ़ा रहे हैं, लेकिन पैठ कम बनी हुई है। इस परिदृश्य में, कृषि मशीनीकरण पर ध्यान केंद्रित करने वाली गैर–बैंकिंग वित्त कंपनियों (एनबीएफसी) क्षेत्र ने एक उल्लेखनीय सफलता की कहानी लिखी है। यह वास्तव में भारत की विविध और उद्यमशीलता की भावना का प्रमाण है। बड़े कृषि बुनियादी ढांचे के वित्त–पोषण से लेकर छोटे किसानों के माइक्रोफाइनेंस तक, इन एनबीएफसी ने समय के साथ नवाचार किया है और समग्र रूप से किसान समुदाय की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के तरीके खोजे हैं। समय के साथ, कृषि–केंद्रित एनबीएफसी/फिनटेक अच्छी तरह से विनियमित होने के लिए विकसित हुए हैं और कई मामलों में, प्रौद्योगिकी, नवाचार, जोखिम प्रबंधन और प्रशासन में सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाया है। इस प्रकार, वाहक के रूप में कार्य करके एवं वित्तीय समावेशन

https://doi.org/10.52151/aet2023471.1621

पर सरकार के एजेंडे को आगे बढ़ाने का कार्य किया है।

कृषि–केंद्रित एनबीएफसी/फिनटेक किसानों की दीर्घकालिक ऋण आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं क्योंकि उनमें से अधिकांश की ग्रामीण भारत में उच्च पैठ है, और उनके ऋण संवितरण का बड़ा हिस्सा केवल छोटे और सीमांत किसानों पर केंद्रित है। सार्वजनिक डोमेन डेटा से पता चलता है कि कुल छोटे और सीमांत किसानों में से केवल 30 प्रतिशत की बैंकों और अन्य औपचारिक क्रेडिट चैनलों तक पहुंच है। किसानों को ऋण प्रदान करने में बैंकों द्वारा सामना किए जाने वाले कुछ मुद्दों में दूर–दराज और दूरदराज के क्षेत्रों तक पहुँचने में कठिनाई और महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी की कमी शामिल है।

इसके अलावा, छोटे किसानों को उधार देने वाली बैंकिंग गतिविधि सीमांत किसानों के लिए उच्च अधिग्रहण और सेवा लागत और ऋण चूक के अधिक जोखिम जैसी विभिन्न सीमाओं से ग्रस्त है। ऐसी अन्य समस्याएं भी हैं जिनका बैंकों को सामना करना पड़ा है, जैसे कृषि–स्तरीय डेटा एकत्र करने में कठिनाई और किसानों के नकदी प्रवाह और क्रेडिट इतिहास जैसी जानकारी प्राप्त करना। यहीं पर कृषि–केंद्रित एनबीएफसी/फिनटेक की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। उन्होंने कृषि क्षेत्र और व्यक्तिगत किसानों में आवश्यक अंतर्दृष्टि प्राप्त करने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाया है ताकि ऋण को निर्बाध और निष्पक्ष रूप से दिया जा सके। वे कम कागजी कार्रवाई और प्रलेखन के माध्यम से किसानों को जल्दी से ऋण प्रदान करते हैं। उन्नत एनालिटिक्स और ग्रामीण बाजार की जानकारी को अपनाने से उन्हें उधार तंत्र में दक्षता लाने और ऋण चुकाने में लगने वाले समय में कटौती करने में मदद मिलती है।

जिन विभिन्न उद्देश्यों के लिए कृषि–समर्पित एनबीएफसी किसान को पैसा उधार देते हैं, उनमें उपकरण और मशीनरी के लिए ऋण, सिंचाई के आधुनिक और कुशल तरीके, और खेती की मूल्य श्रृंखला में विभिन्न अन्य घटक शामिल हैं। उन्होंने भारत के विशाल ग्रामीण हिस्सों में अनौपचारिक ऋण प्रणाली में उपलब्ध 24–60 प्रतिशत की तुलना में ऋण की ब्याज दर को 12–18 प्रतिशत तक कम कर दिया है। ऋण की मांग का अनुमान लगाने के लिए आधुनिक तकनीक का उपयोग, ऋण के उपयोग की दृश्यता, सिंचाई सुविधाओं पर नजर रखना, आदि, किसानों के लिए सटीक उत्पादों और पेशकशों के साथ आने के लिए इन एनबीएफसी द्वारा प्रदान किए जाने वाले विशिष्ट लाभों का एक और सेट है।

यह समय है कि नीति निर्माता ऐसे एनबीएफसी का समर्थन करें जो औपचारिक कृषि वित्तपोषण में आमूलचूल और गहन परिवर्तन लाने के लिए तैयार हैं। ये एनबीएफसी जिस बड़ी चुनौती से निपटने की कोशिश कर रहे हैं, वह है उन सुधारों के तहत समावेशन करना, जो वर्तमान में बैंकों और उनके कृषि ऋण व्यवसाय तक सीमित हैं। नीति निर्माताओं को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कृषि–केंद्रित एनबीएफसी/फिनटेक को सरकारी सब्सिडी योजनाओं जैसे प्रभावी कार्यक्रमों में शामिल किया जाए, जो अब तक केवल बैंकों के लिए उपलब्ध है। यह उन्हें कुशलतापूर्वक उधार देने में सक्षम बनाएगा, और किसानों की ऋण आवश्यकताओं को कम करेगा, जिससे उनकी आय वृद्धि में सहायता मिलेगी। यह कृषि वित्त–पोषण को बढ़ावा देने और भारत को कृषि अर्थव्यवस्था के वैश्विक नेतृत्व पर हावी होने में भी मदद करेगा।